Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

कुशल भारत
सक्षम भारत

कौशल भारत मिशन
पूर्व शिक्षण को मान्यता

“Relevant रहने का मंत्र है- Skill, Reskill और Upskill
ये मंत्र जानना, समझना, और इसका पालन करना, हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।”

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

विषय सूची

परिचय

1. कौशल भारत मिशन 02
2. पूर्व शिक्षण को मान्यता (RPL)* से क्या मिला 04
3. RPL की अब तक की सफलता 06
4. न्याय-संगत भागीदारी सुनिश्चित करना 07
5. 'कुशल भारत, सशक्त भारत'-नए भारत की ओर 16
6. मीडिया में जनजागरूकता 17

परिचय

''सरकारी मान्यता प्राप्त''–इन शब्दों की महत्ता हम सब भली–भाँति जानते हैं। इस देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो यद्यपि देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाती है। इनमें पारंपरिक कौशल या अनौपचारिक उद्यमी जैसे कालीन बुनाई, हथकरघा, आभूषण बनाना, पत्थर पर नक्काशी करना, आवास–निर्माण करना और बढ़ईगिरी शामिल हैं। ऐसे लोगों ने वर्षों तक अनौपचारिक तरीके से कुशलता अर्जित की है जो हमारी गुरु–शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है।

15 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि अनौपचारिक रूप से स्वयं सीखे गए कौशल को हमें औपचारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे हुनर को एक पहचान मिल सके।

''कौशल प्रमाणीकरण के उपरांत युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं और वह बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।''

राष्ट्रीय कौशल नीति-2009 में पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) की परिकल्पना की गई थी लेकिन इसे संगठित तरीके से लागू नहीं किया गया था। वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन प्रारम्भ किया गया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत यह कार्यक्रम नियमित रूप से लागू किया गया। आज RPL को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ताकि युवाओं के अर्जित कौशल को प्रमाणित किया जा सके।

अध्याय-1

कौशल भारत मिशन

2014 से पूर्व कौशल विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व अनेक विभागों में बँटा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि "Our Skilled youth will build the new India of our dream"

प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत देश के युवाओं के कौशल को मानकीकृत ढांचे के तहत प्रमाणित करने का प्रयास किया गया।

कौशल भारत मिशन को 15 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संचालित दीर्घकालिक प्रशिक्षण, अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता के साथ-साथ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण आते हैं। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1.21 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत 7.5 लाख युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ जन शिक्षण संस्थान (JSS) में 14 लाख से अधिक लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भारतीय रेलवे के स्वर्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रेन अटेंडेंट्स को RPL प्रमाणीकरण

इसके अलावा प्रतिवर्ष 25 लाख युवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में, 50 लाख युवा PMKVY में और 25 लाख युवा शुल्क आधारित कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं। NAPS की प्रशिक्षुता एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कौशल कार्यक्रमों में जुड़ने से लगभग एक करोड़ से अधिक युवा प्रतिवर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद कुशल जनशक्ति की आवश्यकता बढ़ी है। युवाओं के कौशल को पहचान कर उन्हें रोजगार के अवसर आसानी से दिए जा सकते हैं। इस तरह के अवसर न सिर्फ हायरिंग और प्रशिक्षण लागत को कम करते हैं, बल्कि उद्यमी की उत्पादकता पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

स्किल इंडिया के अंतर्गत मानकीकृत कौशलीकरण ढांचे के तहत देश भर में युवाओं के कौशल और प्रमाणन में तेजी लाने के प्रयास किए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के द्वारा पूर्व शिक्षण को मान्यता (RPL) के तहत मौजूदा कार्यबल के प्रमाणीकरण को सक्षम बनाया गया है।

अनुभवी कारपेंटरों को उनके अनुभव के लिए स्किल इंडिया की मान्यता

अध्याय-2

पूर्व शिक्षण को मान्यता (RPL) से क्या मिला ?

मुख्य रूप से RPL के तीन उद्देश्य हैं:

- देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क (NSQF) में संयोजित करना।
- रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना।
- असमानताओं को कम करने की ओर प्रयत्न करना।

किसी भी कौशल में पहले से निपुण व्यक्ति अपने अर्जित कौशल को NSQF प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित करवा कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इसमें सभी लाभर्थियों को 12 घंटे का एक अनिवार्य अभिविन्यास प्रदान किया जाता है। इसमें कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन की प्रक्रिया, सॉफ्ट स्किल्स और उद्यमशीलता शामिल है। यदि स्किल गैप हो तो 68 घंटे का एक ब्रिज कोर्स भी कराया जाता है।

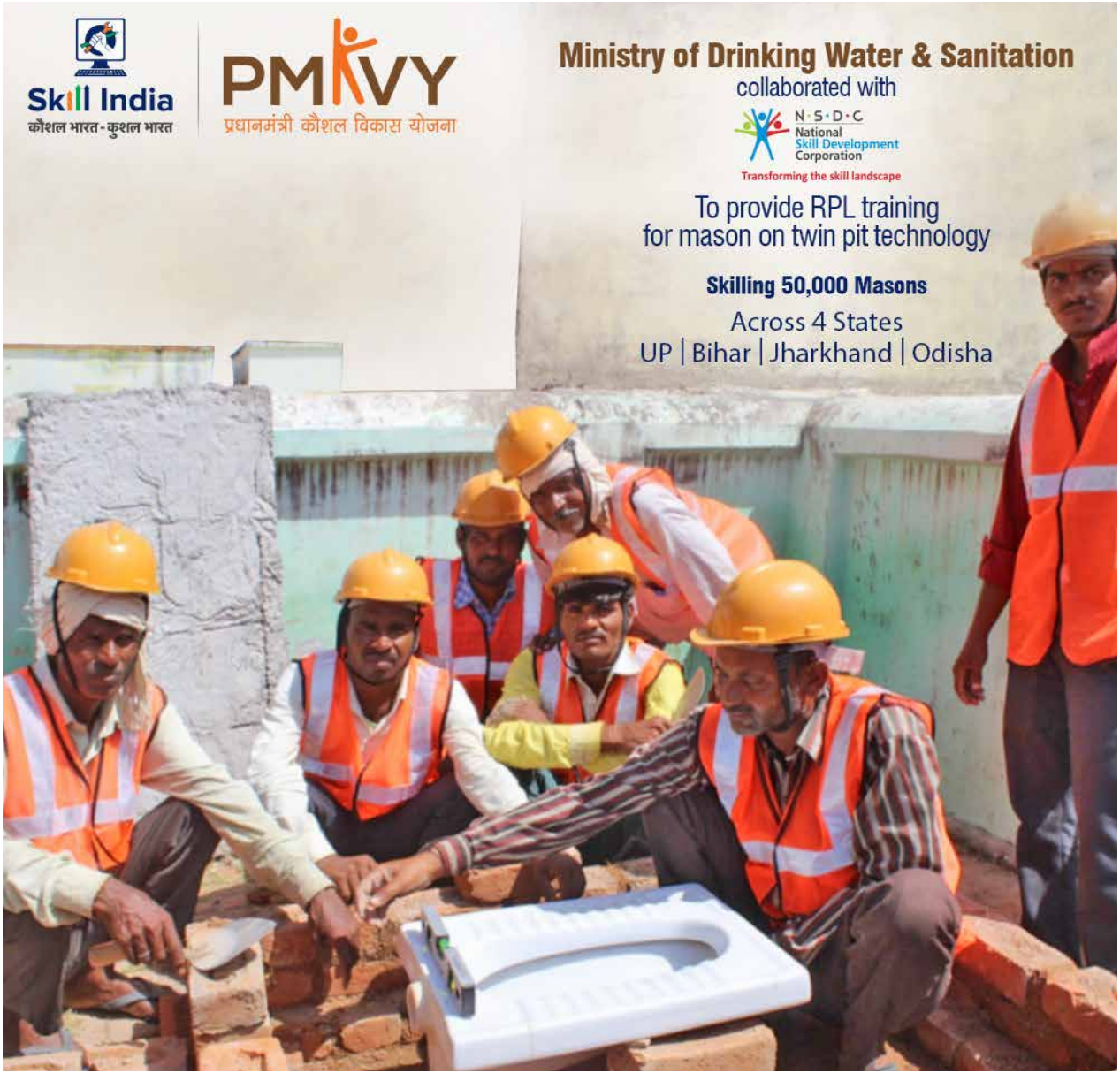

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मिस्त्रियों को
ट्विन पिट टॉयलेट बनाने की ट्रेनिंग और उनके कौशल को मान्यता

अध्याय-3

RPL की अब तक की सफलता

पूर्व शिक्षण को मान्यता (RPL) 2015–2022 के तहत 10 जुलाई 2021 तक 37 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 63 लाख से अधिक लाभार्थी प्रमाणित हो चुके हैं।

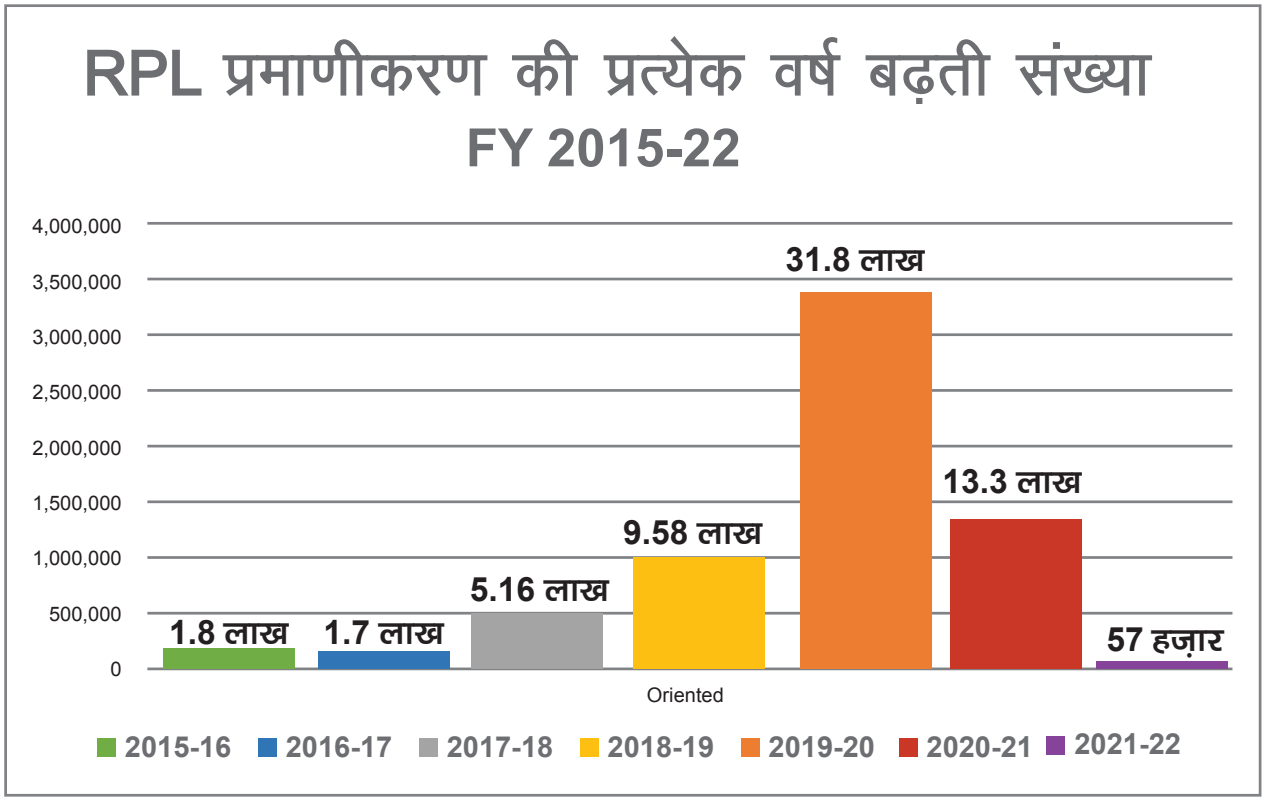

प्रमाणति लाभार्थियों का डाटा ASEEM (Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping) पोर्टल और एप्लीकेशन माध्यम से उद्योगों को उपलब्ध कराया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो बाजार की मांग के अनुसार उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराता है।

अध्याय-4

न्याय–संगत भागीदारी सुनिश्चित करना

राज्यों से सहभागिता

- राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के माध्यम से राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत परियोजनाओं के लिए आन–बोर्ड किए गए थे।
- कारीगर/कामगारों के रूप में लगे 69,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न जॉब रोल्स में प्रमाणित किया गया है।

जयपुर के बुनकरों के स्वयं उनके पूर्व प्रशिक्षण एवं अनुभव को RPL के तहत मान्यता

स्किल्स ऑन व्हील्स – टायर मैकेनिकों के पूर्व अनुभव एवं शिक्षण को मान्यता

ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में युवाओं को मिला प्रमाणीकरण, योग प्रशिक्षकों को भी मिली पहचान

- देश भर के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, 100 से अधिक आकांक्षात्मक जिलों, और 65 से अधिक लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिस्ट जिलों को आच्छादित करने के लिए एक परियोजना आधारित प्रयास किए जा रहे हैं।

उद्योगों की भागीदारी

- उद्योगों में RPL की स्वीकार्यता बढ़ाने और नियोक्ताओं तक सीधे NSQF का विस्तार करने के लिए PMKVY 2016-20 की एक पहल के रूप में बेस्ट इन क्लास नियोक्ता (RPL-BICE) के साथ RPL को लागू किया गया था। RPL-BICE अनेक नियोक्ता/उद्योग भागीदारों को आकर्षित करने में सक्षम हुआ है। RPL-BICE के तहत अब तक 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया जा चुका है।

समर्थ डायमंड कंपनी के कर्मचारियों का RPL-BICE के अंतर्गत कौशल उन्नयनीकरण

BPCL के कर्मचारियों का RPL-BICE के अंतर्गत प्रमाणीकरण

महिलाओं की भागीदारी

परिधान निर्माण से लेकर एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में 9 लाख से अधिक महिलाओं को प्रमाणित किया गया है।

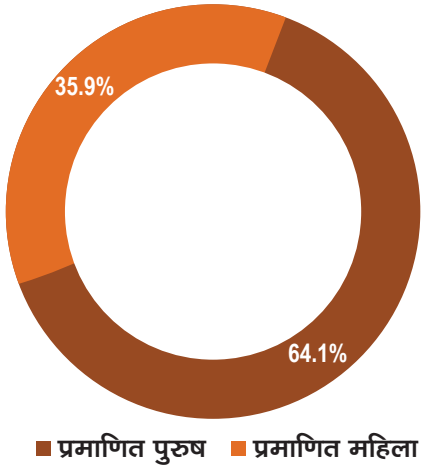

ग्रामीण भागीदारी

4.5 लाख से अधिक अभ्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक ग्रोअर्स, बॉयलर फॉर्म वर्कर, श्रीम्प फार्मर, फार्मिंग के लिए ड्रोन सिमुलेटर एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक पाठ्यक्रमों में भी प्रमाणित किया गया है।

महाराष्ट्र पुणे के पिंपलवाडी सर्कल के कृषि भाइयों और बहनों को ग्रुप फार्मिंग प्रेक्टिशनर का RPL सर्टिफिकेट – महाराष्ट्र एग्री स्किलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 2.82 लाख किसानों का उन्नयनीकरण

बिहार में बिजली के क्षेत्र में RPL के माध्यम से कौशल उन्नयन

पावर सेक्टर स्किल काउंसिल के सौजन्य से भारत सरकार की सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA) स्कीम के अंतर्गत 6 राज्यों में 50,000 से अधिक लाइनमैंन एवं टेक्निकल हेल्परों के जॉब रोल में RPL प्रमाणीकरण

रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के कगार पर सशस्त्र बल कर्मियों को सीखे गए कौशल को उपयोगी बनाने हेतु ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक 60,000 से अधिक सशस्त्र बल सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को प्रमाणित किया गया है।

मीट एट आगरा

आगरा | वरिष्ठ संवाददाता

शुक्रवार को आगरा ट्रेड सेंटर में वैश्विक लेदर, फुटवियर कॉम्पोनेंट एवं मशीनरी फेयर मीट एट आगरा का उद्घाटन करते मेयर नवीन जैन, केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. एमएन पांडेय, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। साथ हैं सांसद एसपी सिंह बघेल, राजकुमार चाहर, उद्यमी पूरन डावर।

प्रदर्शनी — सुबह दस बजे से देखने का मौका

प्रस्ताव — उद्यमियों को भी सक्रिय होना होगा

पहल — आगरा में स्पोर्ट्स शूज का भविष्य

प्रहार — चुनाव में माया का बुरा हाल : स्वामी

पीड़ा — सीएम को बताएंगे आगरा का दर्द

जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट है आगरा फुटवियर : डावर

तमाम पाबंदियों के कारण पिछड़ रहा : एसपी सिंह

उत्पादन को बढ़ावे के लिए है योजनाएं : अकील

अरे वाह! क्या जूता है...

शुक्रवार को मीट एट आगरा में मशीनों की जानकारी लेते उद्यमी।

सबसे ज्यादा निर्यात के लिए गोपाल गुप्ता पुरस्कृत

RPL के अंतर्गत भारतीय सैनिकों की स्किल इंडिया के द्वारा की जा रही मूल्यांकन प्रक्रिया

भारतीय नौसेना के एक्स-सर्विसमेन को RPL के तहत
स्किल इंडिया ट्रेनर बनने के लिए प्रमाणीकरण

कौशल से दें जीवन को एक नई दिशा

नाम	गोकुल नंद साहू
उम्र	81
जगह	कटक, ओडिशा
अनुभव	60 साल
व्यवसाय	गोल्ड स्मिथ इन फिलीग्री आर्ट
RPL के पूर्व आय	70–80 रुपए प्रतिदिन
PMKVY 2016–2020 के अंतर्गत प्रशिक्षण	गोल्ड स्मिथ अकादमी से RPLसर्टिफिकेशन
RPL के बाद आय	4 गुना बढ़ोत्तरी

''मेरे हुनर को मिली इस प्रमाणपत्र के द्वारा पहचान बहुत मायने रखती है। आज तक इतने साल हो गए, कभी भी मुझे कोई मान्यता नहीं मिली, या मेरे कौशल को कोई पहचान नहीं मिली, प्रमाणपत्र की बात तो सोच के ही बाहर थी। मैं आज सब से खुश इंसान हूं। मैंने आधुनिक उपकरणों के साथ काम करना सीख लिया है और यह एक विडंबना है कि मैं ऐसे उपकरणों और तकनीकों का आज तक उपयोग नहीं कर पा रहा था। यदि कर पाता तो मेरी उत्पादकता और आय आज बहुत अधिक हो सकती है। मुझे खुशी है की आज मुझे सही दिशा मिली है।''

RPL प्रमाणीकरण के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि

- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल उम्मीदवारों में से 59% उम्मीदवार, जिन्होंने RPL से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनका मानना है कि RPL उनके कौशल को सशक्त बनाता है और बाजार में उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने में सहायता करता है।
- सम्बोधि रिसर्च एवं कम्युनिकेशन द्वारा प्रस्तुत PMKVY 2-0 की रिपोर्ट के अनुसार, RPL के प्रमाणीकरण के बाद कार्यबल आय में 25% (8,500 रुपये से 11,000 रुपये तक) की बढ़ोतरी हुई है। 35% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि RPL से उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, RPL प्रमाणीकरण के बाद लगभग 47% लोगों ने वेतन में वृद्धि प्राप्त की है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 63% लाभार्थियों ने अपने कार्यस्थल पर उच्चतर स्थान प्राप्त किया है।

टाटा स्टील के कर्मचारियों के पूर्व शिक्षण को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना RPL प्रोग्राम के तहत प्रमाणीकरण

कोरोना महामारी के बाद कौशल उन्नयन और कौशल प्रमाणीकरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज RPL के द्वारा अपने कौशल को प्रमाणित कर उम्मीदवार बेहतर जीवन जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भी स्वीकार किया है कि RPL से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी कौशल महोत्सव में चयनित अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र देते हुए

अध्याय-5

कुशल भारत, सशक्त भारत
नए भारत की ओर

यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ही है कि आज RPL के द्वारा लोगों का जीवन बदल रहा है। RPL न सिर्फ अनौपचारिक कौशल को मान्यता प्रदान कर रहा है, बल्कि उम्मीदवारों को सम्मान दिलाकर औपचारिक मान्यता प्रणाली से भी जोड़ रहा है। हमें विश्वास है कि इस योजना के अंतर्गत कुशल उम्मीदवार अपनी आजीविका को बेहतर कर नए भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने में सक्षम होंगे।

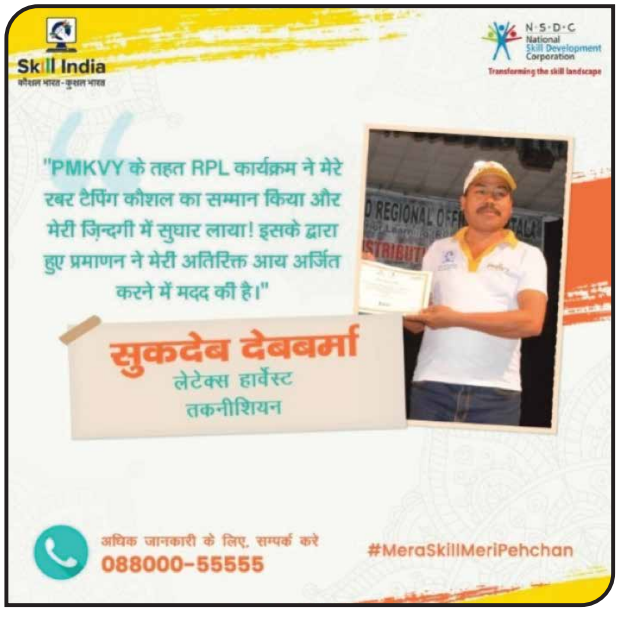

मीडिया में जन जागरूकता

युवाओं के हुनर को मिली पहचान कौशल को मिला प्रमाण पत्र

केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्रनाथ पांडेय ने वीडियो कांफ्रेंस से नियामताबाद व शहाबगंज के युवाओं को किया संबोधित

संवाद न्यूज एजेंसी

चंदौली। जिले के नियामताबाद और शहाबगंज ब्लाक के 160 ग्राम पंचायतों में कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। इसमें चयनित 779 के सापेक्ष 488 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सोमवार को एनआईसी में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। साथ ही युवाओं में प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

जिले की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय की पहल पर पहले चरण में जिले के नियामताबाद व शहाबगंज ब्लाक का चयन किया गया है। दोनों ब्लाकों की 160 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान योजना के बाबत विस्तृत चर्चा की। कहा कि देश की 70 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। ऐसे में कौशल विकास की सफलता के लिए ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल करना जरूरी है। कौशल विकास निगम की ओर से गांवों में युवाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कहा कि ग्राम पंचायतों के योजना में शामिल होने से अभियान को गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण में युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित की जाएगी। युवाओं के लिए आजीविका के स्थायी साधन तलाशे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल भारत के विजन की दिशा में यह एक अहम कदम है। चंदौली के प्रति लगाव रहता है। इसलिए जिले के लोगों को हुनरमंद बनाना प्रमुख उद्देश्य है।

प्रमाण पत्र वितरिण के दौरान एनआईसी में मौजूद डीएम तथा प्रशिक्षणार्थी।

कौशल विकास मिशन से मिला लाभ

लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले कारीगर संजय विश्वकर्मा को कौशल विकास मिशन से काफी मदद मिली। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। बोले कहा कि 15 साल से बढ़ई के तौर पर काम कर रहा था। केंद्रीय मंत्री की पहल के बाद सरकार से सहायता मिली। पेंटर चिराग कुमार ने कहा कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद बैंक से ऋण लेकर रोजगार लगाने में सहूलियत मिलेगी। प्लंबर सुनील कुमार ने बताया कि आजिविका के लिए सरकार की पहल सराहनीय है। अब रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

किसानों को 125 क्विंटल अनाज बेचने की छूट

केंद्रीय मंत्री की पहल पर कृषि प्रधान जनपद के बड़े किसानों को एक बार में 125 क्विंटल तक अनाज क्रय केंद्र पर बेचने की छूट मिल गई है। इससे किसानों के लिए सहूलियत बढ़ गई है। पहले अधिकतम 75 क्विंटल तक का मानक था। इससे बड़े किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सांसद तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने शासन स्तर पर वार्ता की। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में इसे लागू कर दिया गया।

स्किल इंडिया ने प्रारंभ किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, एमएसडीई ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है.इस पहल के द्वाराए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,पीएमकेवीवाई 2016.2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित, घटक के तहतए मांग.संचालित कौशल और अभिविन्यास के माध्यमसे कोविड.19 के बाद प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय जिला कलेक्टरों जिला मजिस्ट्रेटों धृ उपायुक्तों के सहयोग से 125 दिनों के कार्यक्रम के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए इन 6 जिलों में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ.कुछ जिलों में शुरू हो चुका है और बचे हुए जिलों में इसी महीने से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत हो जाएगी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ;एनएसडीसीद्ध पीएमकेवीवाई 2016.20 या राज्य की योजनाओं के तहत मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। लघु अवधि प्रशिक्षण ;एसटीटीद्ध कार्यक्रम के तहत 1₹5 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा हैए और अन्य 1₹5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रिकगनाइजेशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग ;आरपीएलद्ध योजना के तहत प्रमाणित किया जा रहा है। इन जिलों में स्थानीय नौकरियों के साथ.साथ प्रशिक्षण के उद्देश्य से वापसी आने वाले श्रमिकों को एकत्रित करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कौशल मंत्रालय स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा हैए जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित है। ग्रामीण विकास के लिए कौशल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉण् महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा, कौशल सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जाएगा जोस्किल इंडिया मिशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल कर्मचारियों का 70: ग्रामीण भारत से आता है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार ग्रामीण कार्यबल को कुशल बनाने की अति आवश्यकता है ताकि स्किलिंग इकोसिस्टम में विभिन्न भागीदारों के बीच सहजता से तालमेल बनाया जा सके। हमें प्रवासी श्रमिकों पर पड़ने वाले दवाबों को कम करना है और क्षेत्रीय स्तरों पर उद्योग.प्रासंगिक नौकरियों का पुनर्निर्माण करने की अधिक आवश्यकता है ताकि हम खुद को फिर से संगठित करके एक दूसरे के पूरक बन सकें। हम प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने और स्थानीय मांग.संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रमिकों की सामूहिक ताकत हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन चिन्हित जिलों में कौशल प्रशिक्षण और ओरीएन्टेशन कार्यक्रम के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रदाताओं की मान्यता और संबद्धता को प्रकाशित करने और उसके बाद सिस्टम.आधारित लक्ष्यों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आरपीएल प्रशिक्षण पूरा करने वाले श्रमिकों को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित

अमर उजाला ब्यूरो

900 से अधिक श्रमिक सम्मानित

वाराणसी। स्किल इंडिया की ओर से पंचायती राज विभाग के तहत श्रमिकों को रिकगनिशन ऑफ प्रयोर लर्निंग यानी आरपीएल कार्यक्रम (पूर्व कौशल को मान्यता) के श्रमिकों को सम्मानित किया गया। सोमवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने 900 से अधिक ऐसे श्रमिकों को सम्मानित किया, जिन्होंने कौशल प्रमाण के साथ अपने आरपीएल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के द्वितीय चरण के शुभारंभ की घोषणा भी की।

आरपीएल में बड़ागांव और सेवापुरी ब्लाक के 167 ग्राम पंचायतों के श्रमिक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि आरपीएल के माध्यम से, हमारा लक्ष्य देश की पूर्व-मौजूदा कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत ढांचे में संरेखित करना है। प्रमाणन आत्मविश्वास बनाता है, सम्मान लाता है और उम्मीदवारों को मान्यता प्रदान करता है, इसमें कौशल को आकांक्षात्मक बनाने की क्षमता है।

वर्चुअली पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी विचार व्यक्त किया। फूलपुर निवासनी संगीता ने कहा कि आरपीएल प्रशिक्षण से सूखे कचरे से गीले कचरे को अलग करने के महत्व को सीखा और यहां तक कि एक किट भी प्राप्त की इसमें एक यूनिफार्म, मास्क, ग्लव्स और अन्य आवश्यक टूल्स और उपकरण थे। जो हमारे काम करते समय हमें सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक थे।

वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय।

सींगना के आगरा ट्रेड सेंटर में वैश्विक लेदर, फुटवियर कॉम्पोनेंट व मशीनरी फेयर मीट एट आगरा के उद्घाटन सत्र में बोले केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ

जूता उद्योग बढ़ेगा तो कोई बेरोजगार नहीं बचेगा

प्रमाणित किए गए कारीगर | कौशल को मिले वास्तविक सम्मान | आरपीएल की अहम भूमिका | मोबाइल वर्कशॉप की सराहना

भारत को बनाएंगे विश्व में कौशल की राजधानी : महेंद्र नाथ पांडेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि भारत को विश्व में कौशल की राजधानी बनाया जाएगा। भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 80 लाख लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रबर कौशल विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने यहां 17 मोबाइल कौशल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अब उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक मोबाइल कौशल वैन मौजूद रहेगी। यह सड़क के किनारे पंक्चर बनाने व टायर फिटर का काम करने वाले लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देगी। डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि अभी पूर्व अनुभव को मान्यता (आरपीएल) योजना के तहत 35 हजार टायर फिटर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, एक लाख लोगों को यह ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। अकेले यूपी में 40 हजार टायर फिटर को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मोबाइल कौशल वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम में परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने कहा कि अगस्त में वाराणसी मंडल में यह मोबाइल कौशल वैन चलाई गई। आज से प्रदेश के हर मंडल में यह उपलब्ध है। यह ऐसा कौशल विकास केंद्र है जो खुद चलकर मैकेनिक के पास जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण मिलने के बाद युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में प्रिंस, धर्मेंद्र कुमार वर्मा व आशीष वर्मा को टूल किट प्रदान की गई और टायर फिटर का प्रशिक्षण पाने वाले 25 युवाओं को प्रमाणपत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में रबर कौशल विकास परिषद के अध्यक्ष विनोद टी साइमन ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

17 मोबाइल कौशल वैन को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री ने किया रवाना

80 लाख लोगों को अभी तक देशभर में मिली कौशल विकास की ट्रेनिंग

अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक कल्याण मोदी सरकार में ही हुआ। अफवाह फैलाने वाले विपक्ष को मैं चुनौती देता हूं कि वह मोदी सरकार के कार्यों की थर्ड पार्टी जांच करवा ले।

डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री

लखनऊ में शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मोबाइल कौशल वैन को झंडी दिखाकर रवाना करते (बाएं से दाएं) कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया व अध्यक्ष रबर कौशल विकास परिषद विनोद टी साइमन • जागरण

वर्ल्ड स्किल कम्पटीशन की तैयारी पर यूपी खर्च करेगा साढ़े पांच करोड़

कार्यक्रम में उप्र कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वर्ष 2021 में चाइना में होने वाले वर्ल्ड स्किल कम्पटीशन की तैयारी पर यूपी साढ़े पांच करोड़ रुपये खर्च करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) कानपुर से एमओयू होगा। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को 75-75 लाख दे रही है। यूपी द्वारा अपने स्तर से इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना खुशी की बात है।

Union minister flags off mobile vans to reskill auto mechanics

Upskilling Key Agenda Of Centre: Min

Times News Network

Varanasi: Union minister for skill development and entrepreneurship, Mahendra Nath Pandey flagged off Mobile Skill Vans from Varanasi on Sunday for upskilling and certifying tyre fitters across the state under the Recognition of Prior Learning (RPL) programme of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).

Flagged off under 'Saamarth', a reskilling project of Rubber Skill Development Council (RSDC), the mobile vans will take upskilling to automechanics, especially tyre fitters who do not have access to a formal training. Under the programme, fitters will taught to implement best practices and also made aware about health and safety methods to be followed during wheel alignment and changing of tyres.

The 'Saamarth' project of RSDC was approved by MSDE to reskill 10 lakh workforce in rubber sector. The skill council has set a target of 64,000 to be trained in manufacturing, natural rubber plantation and tyre service and maintenance. The mobile vans will cover 75 districts and will reskill more than 39,000 tyre fitters.

Flagging off the vans, Pandey said that upskilling and reskilling, whether by upgrading as per the need of industry or capacity building of the existing workforce to make them more productive, is key agenda of the Central government. Introducing mobile skilling units will help those who cannot reach a formal skilling centre, said the minister.

Later, certificates and kits were distributed among candidates undergoing RPL training. The Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) has collaborated with RSDC for upskilling tyre fitters. RSDC has taken the lead in training workers in rubber plantation and compression moulding operator, tyre fitting, latex harvest technique etc.

ATMA director general Rajiv Budhraja said that tyre fitters play an important role in smooth functioning of a tyre and the entire logistics supply chain as well.

Apart from repairing a damaged tyre, a fitter also plays the role of an adviser, talking to transporters about the condition of the tyre and precautions that need to be taken for improving the life of tyre. RSDC chairman Vinod Simon said that the initiative aims at overall road safety awareness. Tyre services and maintenance is an important part of road safety and economic growth and has a major role in making road transport efficient, he said.

Union minister Mahendra Nath Pandey flags off mobile skill vans in the city on Sunday

Govt to expand skill devpt progs in J&K, Ladakh: BJP

Times News Network

Varanasi: After the abrogation of Article 370 from Jammu and Kashmir and bifurcating it into two Union Territories J&K and Ladakh, the Central government has planned to enhance their traditional crafts and industries through skill development for creating employment opportunities.

"The union ministry of skill development and entrepreneurship would conduct a comprehensive study in which a Special Task Force will be constituted to study the traditional skills of the region, and the existing skill development training setups in J&K and Ladakh will be expanded further," said minister of skill development and entrepreneurship Dr Mahendra Nath Pandey while talking to reporters here on Saturday.

"With these initiatives, people of J&K and Ladakh will feel connected with the country and the world," said Pandey adding that the Article 370 and 35 A kept away J&K, which is rich in traditional skills, from the modern development in rest of the world. Prime Minister Narendra Modi's special emphasis is the development of J&K, he said adding that several steps are being taken in this regard.

"My department will develop the skills of J&K and Ladakh and connect them with the other parts of the country," he said adding that all programmes of skill development would run in J&K and Ladakh to create employment opportunities.

In a first, plumbers, painters and masons to get govt certificates in UP

Pilot Project Launched In Kashi, Chandauli

Rohan.Dua@timesgroup.com

New Delhi: In a first, Union skill development ministry has launched a pilot project to formally certify already-skilled workers in gram panchayats (GP) that will give them "recognition and respect" to use their expertise while working in government and private industries.

The project was rolled out on Monday across 167 GPs in Prime Minister Narendra Modi's constituency Varanasi and neighbouring Chandauli district.

The programme, a joint initiative between World Bank and Centre, is known as Recognition of Prior Learning (RPL) uner the Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP). The implementing agency for the programme is National Skill Development Corporation (NSDC).

Over 900 candidates were awarded the certificates under this programme on Monday while 2,250 have been enrolled for training.

'RECOGNITION & RESPECT'

- Skilled workers in UP to have "respect" certifications
- Joint initiative between World Bank, skill development ministry
- Varanasi, Chandauli chosen as pilot districts
- Programme to recognise and bring respect to skilled workers
- Includes painters, carpenters, sanitation workers, plumbers
- UP Panchayati Raj department to aid Centre

▶7,500 workers, P 7

"आज के दौर में तेजी से बदलते बिज़नेस और बाज़ार के बीच प्रासंगिक रहने का मंत्र है, स्किल, रीस्किल और अपस्किल। इसी विज़न के साथ हम लगातार फ्यूचर-रेडी कार्यबल के निर्माण के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।"

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,भारत सरकार